[1967]_1 एस सी आर _469

जमुना सिंह बनाम बिहार राज्य

सितंबर 22,1966

[वी. रामस्वामी, वी. भियारोवा और रघुदर दयाल, न्यायाधीश]

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (कानून 45, 1860), धारा 436, 109, धाराओं के तहत मुख्य अपराधी की बरी - धारा 436- सहायक की सजा कब और कैसे जायज.

प्रस्तावक को मुख्य अपराधी के साथ एक झोंपड़ी को जलाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436 के तहत धारा 109 के साथ एक अपराध का सिद्धांती भावना कर चुका था। उच्च न्यायालय ने धारा 436 के तहत उन्होंने कही ऐसे एक सह-दोषी को बरी कर दी, लेकिन वे अपराध की धारा 109 के साथ प्रस्तावक की सजा की पुनर्धारा की। इस न्यायालय में विशेष अनुमति से यह जांचने के बाद कहा गया कि मुख्य अपराधी की बरी के बाद भी धारा 436 के अपराध की सहायक की सजा कानूनी नहीं है।

निर्णय: (i) कानून में यह कहा नहीं जा सकता है कि जब अभियुक्त व्यक्ति को दोषी माना गया है कि वह सहायक किसी विशेष अपराध का कृत्य करने के लिए, तो सहायक को उस अपराध की प्राकृतिकता और उस सहायक के द्वारा इस प्रायोजन में कैसे नियमित किया गया था, इस पर निर्भर करेगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत, किसी व्यक्ति को किसी अपराध का कृत्य करने के लिए तीन तरीकों में सहायकी दिया जाता है, जिसमें किसी को किसी कार्रवाई को करने के लिए प्रोत्साहित करना, या उस कार्रवाई को करने के लिए किसी और व्यक्ति के साथ साजिश में शामिल होना; या उस कार्रवाई को करने की योग्यता में मदद करना शामिल है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है या उस द्वारा साजिश में शामिल होता है, तो वह एक ऐसे अपराध को सहायक करता है और धारा 115 या धारा 116 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सहायक के रूप में दोषी होता है, चाहे ऐसा अपराध सहायन हो या न हो। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का सहायकी द्वारा किसी अन्य को उस अपराध को करने में इच्छा से मदद करता है, तो जब उसे उस अपराध का आरोप जिसने वह अपराध किया है, कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ सहायक के आरोप का आश्वासन होना चाहिए। [472 A-क; 473 Al बरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा एम्परर, एल.आर. 52 आई.ए. 40 और फगुन

कांत नाथ बनाम असम राज्य, [1959] सप्प. 2 एस.सी.आर. 1, पर भरोसा किया गया। गल्लू साहू बनाम राज्य के निर्णय ने (1959) एस.सी.आर. 861, को अप्राप्य माना। (ii) वर्तमान केज में धारा 436 के तहत मुख्य अपराधी के खिलाफ जिस व्यक्ति के साथ दर्ज किया गया था, उसको बरी कर दिया गया था और न्यायालयों ने किसी ऐसे आपत्ति का कोई निर्णय नहीं दिया था कि उस आपत्ति को प्रस्तावक और उसके प्रोत्साहन के बदले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया था। इसलिए प्रस्तावक को धारा 436 के तहत धारा 109 के साथ दोषी नहीं माना जा सकता था। [474 B) उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावक ने अपने सह-दोषी को धारा 436 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रोत्साहित किया था। इसलिए उसे धारा 436 के तहत धारा 115 भारतीय दण्ड संहिता के साथ दोषी माना जाना चाहिए। (474 El सजा और दण्ड इस तरह से बदल दिए गए।

आपीलीय द्वारा विशेष अनुमति से आपील दायर की गई थी: आपील क्रिमिनल आपील नंबर 238 ऑफ 1964 I

1963 के क्रिमिनल आपील नंबर 481 में 1964 के जुलाई 27 के न्याय और आदेश की अपील से विशेष अनुमति से।

डी. पी. सिंह, प्रस्तावक के लिए

प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ

द्वारा सुनाया गया न्यायालय का निर्णय:-

रघुबर दयाल, जज: जमुना सिंह अपनी अपील को विशेष अनुमति द्वारा, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, जिसमें उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था और उनकी दोषसिद्धि और सजा **धारा 323 और 436 के साथ धारा 109 आईपीसी के तहत दण्डित किया गया था,** उसके **खिलाफ अपील करते हैं।**

अपीलकर्ता के साथ, चार अन्य व्यक्तियों पर दंगा करने और धारा 323 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया। इनमें से एक जोधा सिंह था, उसे **धारा 436 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया था।** सहायक **सत्र न्यायाधीश ने पांच व्यक्तियों में से एक को अपराध से बरी कर दिया और अन्य चार को धारा 323 आईपीसी के तहत दोषी पाया। उन्होंने जोधा सिंह को भी धारा 436 आईपीसी के तहत दोषी पाया।**

इन चार दोषी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष **दो अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया**। उसने **जोधा सिंह को धारा 436 आईपीसी के तहत के अपराध से बरी किया**, **लेकिन धारा 323 आईपीसी के तहत के दोष की सजा को बरकरार रखा**, **जमुना सिंह की अपील खारिज की गई। वह इस न्यायालय में अपील पर आये हैं।**

अपीलकर्ता के **विद्वान वकील ने धारा 323 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की सजा पर सवाल नहीं उठाया**। उन्होंने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता को **धारा 109 आईपीसी के साथ पढ़ी गई धारा 436 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है,** जब जोधा सिंह जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपीलकर्ता के उकसाने पर **बैशाकी की झोपड़ी में आग लगा दी थी,** उसे आग लगाने का दोषी नहीं ठहराया गया है।

विवाद से निपटने से पहले, हम भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धाराओं का उल्लेख कर सकते हैं।

"**107. कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, कौन**

पहला- किसी भी व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाता है, या.

दूसरा - उस कार्य को करने के लिए किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के साथ शामिल होना, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में और उस कार्य को करने के लिए कोई कार्य या अवैध चूक होती है, या

तीसरा - जानबूझकर किसी कार्य को करने में सहायता करना या गैरकानूनी चूक करना।

स्पष्टीकरण 1: ए. वह व्यक्ति, जो जानबूझकर गलत बयानी करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसका खुलासा करने के लिए वह बाध्य है, स्वेच्छा से कोई कार्य कराता है या प्राप्त करता है, या करवाने या प्राप्त करने का प्रयास करता है, ऐसा करने के लिए उकसाने वाला कहा जाता है उस चीज़ का I

स्पष्टीकरण 2: जो कोई, किसी कार्य के किए जाने से पहले या उसके समय, उस कार्य के किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ करता है, और इस प्रकार उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने में सहायता करता है, ऐसा कहा जाता है।

108. एक व्यक्ति किसी अपराध को दुष्प्रेरित करता है, जो या तो किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो एक

अपराध होगा, यदि अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपराध करने में सक्षम व्यक्ति द्वारा उसी इरादे या जानकारी के साथ किया जाता है। उकसाने वाला I

स्पष्टीकरण 2: दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया जाए।

रेखांकन

(ए) ए ने बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाया। बी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ए, बी को हत्या के लिए उकसाने का दोषी है।

109. जो कोई भी किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, और इस संहिता द्वारा ऐसे दुष्प्रेरण की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। अपराध के लिए प्रावधानित दंड से दंडित किया जाए।

स्पष्टीकरण: कोई कार्य या अपराध उकसावे के परिणामस्वरूप किया गया कहा जाता है, जब वह उकसावे के परिणामस्वरूप किया जाता है। या साजिश के अनुसरण में, या उस सहायता से जो उकसावे का गठन करती है।

115. जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, यदि वह अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप नहीं किया गया है, और इस संहिता द्वारा ऐसे दुष्प्रेरण की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अवधि के लिए जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके लिए दुष्प्रेरक दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप उत्तरदायी है, और जो किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाता है, तो दुष्प्रेरक को चौदह वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सज़ा हो सकती है, और साथ ही दुष्प्रेरक को कारावास भी हो सकता है। जुर्माना लगाया जा सकता है I

कानून में कहा नहीं जा सकता कि यदि किसी काम को करने के लिए उकसाने के परिणामस्वरूप उस काम को करने वाला व्यक्ति निर्दोष पाया गया है, तो किसी व्यक्ति को किसी अपराध के उकसाने के लिए कभी भी दोषी नहीं कहा जा सकता है। उकसाने वाले की दोषिता का प्रश्न उस काम की प्रकृति और उकसाने का तरीका पर निर्भर करता है। **धारा 107 आईपीसी के तहत, एक व्यक्ति किसी काम को करने का अबेट करता है तीन तरीकों**

में, जो हो सकते हैं: किसी को किसी काम को करने के लिए उकसाता है; या किसी और व्यक्ति के साथ किसी साजिश में शामिल होता है उस काम को करने के लिए, या उस काम को करने की इच्छापूर्वक सहायक होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को उकसाता है या किसी और के साथ साजिश में शामिल होता है किसी ऐसे काम के लिए जो एक अपराध है, तो वह ऐसे अपराध को उकसाता है और उसे **धारा 115 या धारा 116, आईपीसी के तहत उकसने का दोष होता है,** भले ही उकसाने के परिणामस्वरूप वह अपराध किया जाए या नहीं। उकसने के अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि उकसाने वाले काम को किया जाना चाहिए। **यह आईपीसी की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 और उसके चित्रण (ए) से स्पष्ट है।**

बरेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर में, यह कहा गया था:

"उकसाने में उकसाए गए अपराध का वास्तविक कमीशन शामिल नहीं है। यह एक अलग अपराध है।"

इस न्यायालय ने इसे दोहराया और **फागुना कांता नाथ बनाम असम राज्य**

भारतीय कानून के तहत दुष्प्रेरण के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराध किया ही गया हो। एक व्यक्ति दुष्प्रेरक के रूप में दोषी हो सकता है, चाहे अपराध किया गया हो या नहीं।"

वर्तमान मामले में, कहा जाता है कि अपीलकर्ता ने **जोधा सिंह को धारा 436 आईपीसी के तहत शरारत का अपराध करने के लिए उकसाया था। जोधा सिंह को धारा 436 के तहत के दोष से बरी कर दिया गया है।** इसलिए कहा जा सकता है कि उसने बैशाकी के झोपड़ी को नहीं जलाया। अपीलकर्ता द्वारा जोधा को धारा 436 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए उकसाना धारा 436 के तहत अपराध को बढ़ावा देने के समान है और इसलिए वह धारा 115 आईपीसी के तहत उकसाने के अपराध का दोषी होगा क्योंकि जोधा सिंह ने अपराध नहीं किया था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि वास्तव में बैशाकी की झोपड़ी में किसी ने आग लगा दी थी, लेकिन अपीलकर्ता के उकसाने पर किसी अन्य द्वारा आग लगाने से अपीलकर्ता आईपीसी की **धारा 109 के तहत उकसाने का दोषी नहीं होगा क्योंकि किसी अन्य द्वारा आग लगाना नहीं था। उकसावे के परिणाम में I इसलिए अपीलकर्ता धारा 109 के साथ पठित धारा 436 आईपीसी के तहत दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी नहीं होगा, लेकिन**

धारा 115 आईपीसी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 436 के अपराध का दोषी होगा क्योंकि धारा 436 आईपीसी के तहत अपराध दंडनीय है आजीवन कारावास के साथ I

यह केवल उस व्यक्ति के मामले में है जो जानबूझकर किसी अन्य को उस अपराध को करने में सहायता करके अपराध के लिए उकसा रहा है, उसके खिलाफ उकसाने का आरोप विफल होने की उम्मीद की जाएगी जब जिस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है उसे उस अपराध से बरी कर दिया जाता है। **फागुना कांता नाथ का मामला**,1959 यह बताता है। उस मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ, पृष्ठ 7पर , मामले में अंतर स्पष्ट रूप से सामने लाएं के एक ओर दूसरे को उकसाने या किसी अन्य के साथ साजिश में शामिल होने वाले व्यक्तियों की और दूसरी ओर किसी व्यक्ति को किसी निश्चित अपराध को करने में सहायता करने की। **अवलोकन हैं :**

यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता ने खलीलुर रहमान को अवैध परितोषण की मांग करने के लिए उकसाकर अपराध को बढ़ावा दिया; न ही अभियोजन पक्ष ने एस के तहत अपराध करने के लिए अपीलकर्ता और खलीलुर रहमान के बीच साजिश का मामला स्थापित किया है या साबित किया है। धारा 161. न्यायालय के निष्कर्षों पर अपीलकर्ता ने खलीलुर रहमान के लिए और उसकी ओर से धन प्राप्त किया और शिकायतकर्ता का साक्ष्य यह है कि खलीलुर रहमान ने उससे अपीलकर्ता को धन सौंपने के लिए कहा था। यदि खलीलुर रहमान को बरी कर दिया जाता है और इसलिए धारा 161 **के तहत अपराध नहीं किया गया माना जाता है, तो इस मामले में किसी भी कार्य या चूक द्वारा जानबूझकर अपराध में सहायता करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।**

गल्लू साह बनाम बिहार राज्य, के रूप में रिपोर्ट किया गया मामला: नीचे न्यायालय द्वारा संदर्भित, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। कहा जाता है कि एक **बुदी** ने उकसाने पर एक झोपड़ी में आग लगा दी थी गल्लू साह। **बुदी को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था**। आईपीसी की धारा 109 के साथ पठित धारा 436 के तहत अपराध के लिए **कैलू साह की दोषसिद्धि की उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी**। इस न्यायालय ने इस तर्क को **खारिज कर दिया कि गल्लू साह की सजा कानून की दृष्टि से खराब थी**। इसने इसे सही माना क्योंकि झोपड़ी में आग गैरकानूनी सभा के एक व्यक्ति द्वारा लगाई गई थी, जिसमें **कैलू साह सदस्य था**। न्यायालय ने पृष्ठ 866 पर अवलोकन किया।:

"मामले में दिए गए निष्कर्षों पर हमें ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने सुश्री रासमणि की झोपड़ी में आग लगाई, वह उन व्यक्तियों में से एक होगा जो गैरकानूनी सभा के सदस्य थे और उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वर्तमान अपीलकर्ता का आदेश पर। हमारा मानना है कि यह मानना बहुत अवास्तविक है कि जिस व्यक्ति ने सुश्री रासमणि की झोपड़ी में आग लगाई, उसने वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दिए गए आदेश की परवाह किए बिना या स्वतंत्र रूप से ऐसा किया। ऐसा निष्कर्ष, हमारे राय, अवास्तविक होगी और मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग होगी और यह जोड़ना आवश्यक है कि अपीलकर्ता का मुकदमा चलाने वाले विद्वान सहायक सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया था। जैसा कि हमने पढ़ा है विद्वान न्यायाधीश के निष्कर्षों से हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने पाया कि जिस व्यक्ति ने सुश्री रासमणि की झोपड़ी में आग लगाई थी, उसने अपीलकर्ता के उकसावे के परिणामस्वरूप ऐसा किया था।"

वर्तमान मामले में, यह है नीचे दिए गए न्यायालय का कोई निष्कर्ष नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लगाई गई थी जो जमुना सिंह के साथ घटना में भाग ले रहा था और उसकी शह पर तीन कथित सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने भाग लिया था घटना में I निचली अदालत के निष्कर्षों के अनुसार जोधा सिंह और जमुना सिंह ने घटना में भाग लिया और जोधा सिंह ने झोपड़ी में आग नहीं लगाई। इससे यह माना जा सकता है कि बैशाकी की झोपड़ी में जमुना सिंह के उकसावे पर किसी ने आग लगाई थी।

परिणाम यह है कि आईपीसी की धारा 109 के साथ पठित धारा 436 के तहत जमुना सिंह की दोषसिद्धि कानून की दृष्टि से सही नहीं है।

जमुना सिंह द्वारा जोधा सिंह को बैशाकी की झोपड़ी में आग लगाने के लिए उकसाना उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित माना जाता है और इसे आईपीसी की धारा 115 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 436 के तहत अपराध बनाता है। धारा 436 के तहत जमुना सिंह को दोषी ठहराया गया है। आईपीसी की धारा 109 को कानूनी तौर पर धारा 436 के तहत धारा 115 आईपीसी के साथ पढ़ा जा सकता है, जिसमें बाद वाला एक छोटा अपराध है।

अपीलकर्ता को धारा 436 के साथ धारा 109 आईपीसी के तहत आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और धारा 436 के साथ धारा 115 आईपीसी के तहत अपराध सात साल तक की कैद और जुर्माने से दंडनीय है। सजा में कमी जरूरी है

परिणामस्वरूप, हम धारा 323 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर देते हैं और धारा 436 के तहत धारा 109 आईपीसी के साथ पढ़ी गई उसकी सजा के संबंध में इसे स्वीकार करते हैं, जिसे हम धारा 436 के तहत एक में बदलकर संशोधित करते हैं। आईपीसी की धारा 115 के साथ पढ़ा जाए और सजा को घटाकर चार साल के कठोर कारावास में बदल दिया जाए।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई

एल.आर. 52 आई.ए. 40,53

1959 सप्लिमेंट2 एस.सी.आर 1,5

1959 सप्लिमेंट2 एस.सी.आर 1

1959 एस.सी.आर 861

शुभम सिंह अधिवक्ता द्वारा अनुभव किया गया अनुवाद,

जो जिला और सत्र न्यायालय, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में अभ्यास कर रहे हैं।